3. बाजार भाव तय करते समय भूमि बिक्री के सबसे अधिक के भाव का भी ध्यान रखा जाय ।

सरकार से प्रार्थना है कि मांगों को ध्यान में रखते हुए ही संशोधन का विधेयक पुरस्थापित और पास करें ।

(vii) RE. SAFETY MEASURES FOR FISHERMEN ON COASTS

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North): Thousands of fishermen living along the Western Coast line, particularly Northern Maharashtra and Gujarat were victims of the vicious fury of a cyclone that hit the coast in November. Apart from the damage done to property and implements, more than a hundred fishermen lost their lives on the seas. Many were caught in the cyclone and quite a few died for lack of adequate warning. In my own constituency in Vasai and Palghar 19 fishermen lost their lives when their boat *Vaibhar* disappeared and five from Dandhi in Palghar lost their lives. There are crores of fishermen living along our Western and Eastern coast lines who have to go out to the sea for coastal or deep sea fishing who are exposed to the fury of such cyclones. The West Coast and Orissa, Andhra, Tamil Nadu and other areas in the East Coast are particularly vulnerable to cyclones that lash the coast every year. Technological advance has made it possible to collect and disseminate meteorological data. The Government should therefore take adequate steps:

(1) to set up an early warning system.

(2) to disseminate this information on the wireless.

(3) to make it compulsory for all motorized boats that go far into the sea to carry wireless receiving sets, and provide boats with such sets.

(4) create a special section that can, in emergencies, draw upon the services of the Coast Guard, Customs Patrol Boats and the Navy to warn and to rescue boats that are at sea, and

(5) introduce a special insurance scheme to provide group insurance to fishermen in fishing communities.

I hope the Government will take expeditious steps in this regard.

(viii) SITUATION ARISING OUT OF RETRENCHMENT OF LABOURERS OF J. K. SYNTHETICS, KOTA (RAJASTHAN)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): सभापति महोदय, राजस्थान में कोटा स्थित जे. के. सिंथेटिक्स ने लगभग तीन हजार मजदूरों की छटनी करके नौकरी से निकाल दिया है, जिनमें अनेक श्रमिकों का अवधि काल 20 वर्ष तक का है । इस विशाल स्तर पर छटनी का कार्य जनवरी के दूसरे सप्ताह व फरवरी के प्रथम सप्ताह के बीच किया गया है । इस छटनी के कारण बेरोजगार हुए तीन हजार श्रमिकों पर आश्रित बीस हजार व्यक्तियों के समक्ष दो समय रोटी खाने तक की समस्या पैदा हो गई है। मालिकों ने इस छटनी का कारण कारखाने में नुकसान होना बताया है, जो नितान्त असत्य है, जबकि गत समय में उक्त कारखाने ने करोड़ों रुपये का लाभ कमाया है । उक्त कारखाने के मालिकों ने इस छटनी के पूर्व राज्य सरकार से भी पूर्व अनुमति नहीं ली जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एन) में लेना आवश्यक था और इस प्रकार मालिकों ने धारा 25 (क्यू) के अधीन अपराध किया है । परन्तु दुःख है कि सरकार ने मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । शत प्रतिशत मजदूरों को ले आफ के नाम पर बिजली कटौती की आड में कारखाने से बाहर खदेड़ दिया और इसी मध्य इतने विशाल स्तर पर मजदूरों की छटनी कर दी। इस छटनी के कारण केवल श्रमिकों में ही नहीं अपितु समूचे क्षेत्र के अन्दर असुरक्षा पैदा हो गई है । राज्य सरकार अभी तक मौन है । ऐसी स्थिति में श्रम मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य देकर सरकार की स्थिति को स्पष्ट करें ।

15.17 hrs.

RAILWAY BUDGET, 1983-84—GENERAL DISCUSSIONS—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, we take up General discussion on the Railway Budget,